

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1483
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी अवसंरचना में सुधार पर 'अमृत' योजना का प्रभाव

1483. श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना का शहरी अवसंरचना जैसे जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों में सुधार पर क्या प्रभाव है;

(ख) तमिलनाडु सहित देश में उक्त योजना के तहत लाभान्वित शहरी परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा अवसंरचना के विकास में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त योजना के तहत कितने शहरी परिवारों को नल जन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ङ) देश भर के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज नेटवर्क में क्या सुधार किए गए हैं;

(च) सरकार द्वारा 'अमृत' शहरों में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(छ) अमृत योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति जानने के लिए मौजूद निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ज) उक्त योजना के अंतर्गत किए गए किसी भी हालिया मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या रहे हैं; और

(झ) सरकार द्वारा विलंब और अक्षमताओं को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को 25 जून 2015 को देश भर में चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) में शुरू किया गया

था। यह मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; तूफानी वर्षा जल निकासी; हरित क्षेत्र और पार्क; तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 77,640 करोड़ रु. के अनुमोदित योजना आकार की तुलना में 83,574 करोड़ रु. की 6,010 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 79,046 करोड़ रु. के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं।

अमृत मिशन के अंतर्गत राज्यों के साथ तालमेल करते हुए 139 लाख के लक्ष्य की तुलना में 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/सर्विस किए गए); 145 लाख के लक्ष्य की तुलना में 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/सर्विस किए गए) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए परिवारों सहित) प्रदान किए गए हैं; 19,598 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क और 64,463 किलोमीटर जलापूर्ति नेटवर्क का निर्माण गया है; 4,447 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज शोधन क्षमता (एसटीपी) और 4,695 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (डब्ल्यूटीपी) का विकास किया गया है; 1,413 किलोमीटर नालियों का निर्माण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 3,678 जगहों पर जल-भराव की समस्या समाप्त कर दी गई है; 5,077 एकड़ हरित क्षेत्र, 430 किलोमीटर पैदल यात्री मार्ग और 43 किलोमीटर साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं। अमृत और इसके साथ तालमेल के अंतर्गत प्रदान किए गए राज्य-वार नल और सीवर कनेक्शन (तमिलनाडु सहित) का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(छ) से (झ): अमृत दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के अन्तर्गत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। साथ ही, अमृत के कार्यान्वयन को तेज करने के उद्देश्य से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल नल कनेक्शनों के प्रावधानों की प्रगति और परियोजना-वार परिणामों पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित अमृत ऑनलाइन पोर्टल है।

नीति आयोग ने जून 2020 में अमृत योजना सहित शहरी परिवर्तन क्षेत्र की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन पर समीक्षा की थी। इस अध्ययन में कवरेज, सार्वभौमिक डिजाइन का समावेश, महिलाओं को मुख्यधारा में लाना, गरीब समर्थक रूपरेखा तैयार करना, प्रवासन और लाभार्थी लक्ष्यीकरण जैसे प्रमुख मापदंडों का मूल्यांकन किया गया। इस योजना के तहत कार्य निष्पादन संतोषजनक बताया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों सहित सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

"शहरी अवसंरचना में सुधार पर अमृत का प्रभाव" के संबंध में 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1483 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

नल कनेक्शन की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्षित परिवार	अमृत और तालमेल के तहत		
			उपलब्ध कराए गए नये नल कनेक्शन	पुनर्वास परियोजनाओं से लाभान्वित परिवार	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,705	7,198	-	7,198
2	आंध्र प्रदेश	7,28,997	3,52,969	67,610	4,20,579
3	अरुणाचल प्रदेश	1,785	4,312	-	4,312
4	असम	1,08,447	72,497	-	72,497
5	बिहार	8,24,823	7,04,788	-	7,04,788
6	चंडीगढ़	24,731	20,000	1,56,434	1,76,434
7	छत्तीसगढ़	3,70,151	3,09,871	-	3,09,871
8	दादरा एवं नगर हवेली	5,895	22,459	-	22,459
	दमन और दीव	7,528	7,000	-	7,000
9	दिल्ली	1,82,196	27,52,255	-	27,52,255
10	गोवा	400	2099	-	2,099
11	गुजरात	1,54,495	6,40,667	14,53,582	20,94,249
12	हरियाणा	2,73,670	3,62,888	-	3,62,888
13	हिमाचल प्रदेश	13,003	17,773	8,903	26,676
14	जम्मू और कश्मीर*	1,07,674	170	77,000	77,170
15	झारखंड	3,61,170	2,99,296	-	2,99,296
16	कर्नाटक	12,89,119	9,20,304	-	9,20,304
17	केरल	1,53,387	1,94,070	4,62,582	6,56,652
18	लद्दाख		1,620	-	1,620
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	10,09,765	6,07,779	8,32,873	14,40,652
21	महाराष्ट्र	19,83,405	11,73,032	37	11,73,069
22	मणिपुर	33,867	28,947	-	28,947
23	मेघालय	7,170	15,143	-	15,143
24	मिजोरम	12,127	56,535	-	56,535
25	नागालैंड	32,881	4,265	1,250	5,515
26	ओडिशा	2,91,204	5,18,395	-	5,18,395
27	पुदुचेरी	7,607	5,250	-	5,250
28	पंजाब	4,59,365	2,53,589	-	2,53,589
29	राजस्थान	6,66,761	4,45,361	-	4,45,361
30	सिक्किम	4,754	3,300	607	3,907
31	तमिलनाडु	16,15,641	16,06,924	-	16,06,924
32	तेलंगाना	9,01,031	2,57,237	2,96,967	5,54,204

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्षित परिवार	अमृत और तालमेल के तहत		
			उपलब्ध कराए गए नये नल कनेक्शन	पुनर्वास परियोजनाओं से लाभान्वित परिवार	कुल
33	त्रिपुरा	20,130	38,620	-	38,620
34	उत्तर प्रदेश	7,02,907	9,29,493	-	9,29,493
35	उत्तराखंड	56,347	79,538	-	79,538
36	पश्चिम बंगाल	14,61,620	16,50,127	11,33,551	27,83,678
	कुल	1,38,76,758	1,43,65,771	44,91,396	1,88,57,167

सीवरेज/सेप्टेज के माध्यम से कवरेज की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्ष्य	अमृत और तालमेल			
			उपलब्ध कराए गए नये सीवर कनेक्शन	सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या	पुनर्वास परियोजनाओं से लाभान्वित परिवार	सीवर कनेक्शन और सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किए गए परिवार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,525			-	-
2	आंध्र प्रदेश	1,30,580	1,01,116	2,98,800	-	3,99,916
3	अरुणाचल प्रदेश	11,898		16,000	-	16,000
4	असम	-			-	-
5	बिहार	1,76,748			-	-
6	चंडीगढ़	-	20,000		1,56,434	1,76,434
7	छत्तीसगढ़	6,42,976	43,118	3,22,099	-	3,65,217
8	दादरा एवं नगर हवेली	-	6,211	19,253	-	25,464
	दमन और दीव	8,856	4,134		-	4,134
9	दिल्ली	1,65,633	21,55,226		-	21,55,226
10	गोवा	3,521	1982		-	1,982
11	गुजरात	23,17,426	5,25,576		25,59,150	30,84,726
12	हरियाणा	2,64,923	3,85,076		-	3,85,076
13	हिमाचल प्रदेश	23,006	25,450	1,760	11,710	38,920
14	जम्मू और कश्मीर*	2,65,802	67,650	2,64,642	-	3,32,292
15	झारखंड	4,58,774	13,000	20,000	-	33,000
16	कर्नाटक	14,34,839	7,08,638		-	7,08,638
17	केरल	2,18,023	3,046	3,73,572	3,358	3,79,976
18	लद्दाख (जम्मू और कश्मीर के साथ)			1,620	-	1,620
19	लक्षद्वीप	-			-	-
20	मध्य प्रदेश	8,52,690	4,02,139		-	4,02,139
21	महाराष्ट्र	11,39,054	4,44,936		30	4,44,966
22	मणिपुर	57,764	4,000		-	4,000
23	मेघालय	31,025		31,000	-	31,000
24	मिजोरम	30,317			-	-
25	नागालैंड	32,881		30,520	-	30,520
26	ओडिशा	2,17,489	1,36,401	2,77,776	-	4,14,177
27	पुदुचेरी	68,463	13,650	2,304	-	15,954
28	पंजाब	2,69,064	1,21,218		-	1,21,218
29	राजस्थान	11,28,812	5,97,318	10,180	7,550	6,15,048
30	सिक्किम	9,509	17,400		-	17,400

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्ष्य	अमृत और तालमेल			
			उपलब्ध कराए गए नये सीवर कनेक्शन	सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या	पुनर्वास परियोजनाओं से लाभान्वित परिवार	सीवर कनेक्शन और सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किए गए परिवार
31	तमिलनाडु	27,04,442	25,20,304		-	25,20,304
32	तेलंगाना	7,24,967	87,570		-	87,570
33	त्रिपुरा	40,260	600		-	600
34	उत्तर प्रदेश	5,37,517	8,89,268	9,73,600	-	18,62,868
35	उत्तराखंड	1,07,059	56,914	18,000	-	74,914
36	पश्चिम बंगाल	4,06,006	1,84,215		-	1,84,215
	कुल	1,44,93,849	95,36,156	26,61,126	27,38,232	1,49,35,514